

समय माया



R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DILLW&PM

वर्ष 13 अंक 41

प्रति सोमवार इंदौर, 13 से 19 मई 2019

पृष्ठ 8

मूल्य 2/- रुपए

भाजपा का घोषणा पत्र विश्लेषण मोदी के एजेंडे से रोजगार गौमाता हिंदू संस्कृति हिंदुत्व मूल मुद्दे गायब

यदि मोदी जीत गया तो पूरा रेलवे का, पूरी विद्युत मंडल कंपनियों का, सड़कों का, पानी का सत्ता में आ जा जाने पर निजीकरण कर दिया जाएगा। 50% राष्ट्रीय राजमार्ग नितिन गडकरी के स्वामित्व या साझेदारी में हैं।

पीने पानी के लिये हर प्रदेश में जल निगम बना दिये गये हैं। जो स्मार्ट मीटर से प्रिपेड भुगतान पर मिलेगा। पैसा खत्म पानी बंद। साथ ही देश के पांच करोड़ छोटे दुकानदारों से लेकर ठेले वालों खोमचे से सड़कों पर सज्जी बेचने वालों सब को खत्म कर दिया

मोदी के अंध भक्त तैयार रहें कटोरा खरीद कर चौराहों पर भीख मांगने के लिए

जाएगा। ताकि अंबानी अदानी टाटा बिरला वालमार्ट, आई टी सी के शॉपिंग मॉल्स में आम आदमी खरीदी करने जाए और उनका मोटा लाभ करवाएं। पांच रु. 10 किलो का टमाटर आपको रु. 100 किलो में ले, आलू रु. 50 किलो मिले गेहूं रु. 5000 कुंटल। अगले 5 साल में खरीदने के लिए तैयार

रहें। वह भी आपको छोटी दुकानों पर कुछ नहीं मिलेगा सारी छोटी दुकान दार क्योंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में इन सब को समाप्त कर केवल शॉपिंग मॉल्स में पूरा मिलावटी महंगा बांसी और समय बाधित माल बेचकर मोटा पैसा कमाने की तैयारी कर दी गई है। अब जब सारे छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे तो इन 4-5 कंपनियों के अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, वाल मार्ट, हिन्दुस्तान लीवर, आई टी सी के शॉपिंग मॉल्स अगले 5 साल में अपनी कीमतों पर माल बेचेंगे। (शेष पेज 2 पर)

नोटबंदी में लाखों-करोड़ नोट छापकर बाले-बाले बांटे गए रिजर्व बैंक को जागीर मान की चहुं दिशी बर्बादी

देश के बैंक रिजर्व बैंक को कठपुतली बना अपने पूंजीपति बापों का लाखों करोड़ का ऋण माफ कर उसकी भरपाई रिजर्व बैंक से करवाई। रिजर्व बैंक के 268 करोड़ के सोने को जो देश के कई स्थानों पर था चुपचाप बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी कर दिया गया। देश के समाप्त होते विदेशी मुद्रा कोष में डाला गया।

घोर भ्रष्ट गुजराती मोदी ने देश का प्रधानमंत्री बनते ही देश की सारी संपत्तियों को पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनी के इशारे पर काले धन की आड़ में रिजर्व

बैंक आदि को अपने बाप की जागीर मानकर चारों तरफ लूटपाट का घोर तांडव मचा दिया। जो उसका बिना कानूनी उलझन के आसान



शिकार हो सकते थे। उनका भरपूर चहुंदिशी दोहन किया। काले धन को खत्म करने की आड़ में, पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनी

के मोटे लाभ के लिए उसने नोटबंदी की तैयारी तो सन 2015 में ही कर ली थी। ताकि काले धन की आड़ में व्यापारियों, दुकानदारों, छोटे उद्योगों, आम लोगों के हाथ से नगदी छुड़ा कर उनके व्यापार को नष्ट कर दिया जाए और उस पर एकाधिकार जमा कर जनता को यूरोप की तरह से आसानी से अपने चंगुल में फंसा कर उनका भरपूर शोषण किया जाए। जो पूंजीवादी राक्षसी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण धिनौना कृत्य होता है।

(शेष पेज 7 पर)

भविष्य की नींव इतिहास की बुनियाद पर रखी जाती है

हर प्रकार के षडयंत्र रचे, हर कदम कदम जनता को लूटने बर्बाद करने



पूंजीपतियों के इशारे पर उनके फायदे के लिए देश में नोट बंदी, जीएसटी लगाकर, देश में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, पटेल प्रतिमा, का कार्य 10 गुना ज्यादा लागत के राष्ट्रीय राजमार्ग, लंबे चौड़े पुल निर्माण आदि अपने फायदे के लिए किए गए। दूसरी तरफ जनता से बैंकों से, महंगे पेट्रोल, हर बैंकों में 5 लेनदेन के बाद रु196/- का भारी चार्ज लगा कर लूट, पूंजीपतियों के लाखों करोड़ के डूबंत की वसूली कर बैंकों को बचाया जा रहा। पूरे देश में जानबूझकर अच्छी बनी सड़कों को तोड़फोड़ कर मात्र कमाई के लिए जनता को परेशान किया जा रहा।

मोदी ने पिछले 5 सालों में जनता से हर तरह, हर कदम से

लूट की। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 30 से \$50 पेट्रो क्रूड की कीमतों पर भी भारत में 2 से 5 गुना पेट्रोल डीजल गैस पर वसूली की गई। पेट्रोल सौ के, डीजल रु 90/- के पार और गैस रु. 980/- पार पहुंचा कर रु हजारों करोड़ प्रतिदिन की भारी वसूली की गई।

देश में नोटबंदी के कारण 2 माह तक 40 करोड़ लोग 3 माह तक नगदी के अभाव में पूर्णता बेरोजगार हो गए। केवल ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में 40लाख ट्रक, 40लाख मिनी व बड़ी बसें, ऑटो, 50 लाख से ज्यादा छोटे लघु व्यापारी, उद्योग धंधे तालाबंदी के शिकार हो देश के उत्पादन को पूर्णता ठप कर दिया गया। जिसके घाव और परेशानियों से अभी तक भी देश उबर नहीं सका।

30 करोड़ गरीबों के जनधन खाते बैंकों में खुला कर न्यूनतम बैलेंस, सेवा शुल्क आदि के नाम पर गरीबों का रूप 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा हजम कर लिया गया ताकि पूंजी पतियों को दिए लाखों करोड़ सी डुबती बैंकों की माली हालत सुधारने की कोशिश की गई।

(शेष पेज 2 पर)

इंदौर की जनता ने इंदौर को सफाई में नंबर वन बनाया है

अब लोकसभा चुनाव में भी इंदौर की जनता राजनीति के दल-दल में आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों की सफाई कर कर्मठ उच्च शिक्षित, ईमानदार, देश के और विश्व की जनता के हितों के लिए समर्पित पत्रकार अजमेरा एस प्रवीण कुमार को चुनें

इंदौर की जनता से अपील

2019 के लोकसभा चुनाव में आप अपना अमूल्य मत आपके ही नगर के उच्च शिक्षित, कर्मठ पत्रकार जो साप्ताहिक समय माया समाचार पत्र के व www.samaymaya.com साइट के प्रधान संपादक है। पिछले 20 वर्षों से लगातार न केवल क्षेत्रीय प्रादेशिक, राष्ट्र व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व की जन, जल, जीव-जगत पर्यावरण के लिये लगातार सत्ता, पूंजीपतियों से आमजन, गरीबों, मजदूरों, किसानों के हित में संघर्ष कर रहे हैं। जिसकी सत्यता आप www.samaymaya.com की साइट पर देख सकते हैं।



निवेदन है अपने समाज, राष्ट्र व विश्व के सुखद, समृद्ध, शक्तिशाली शांतिपूर्ण भविष्य के लिये अपना अमूल्य वोट

ट्रेक्टर चलाता किसान वाला बटन दबाकर अजमेरा एस प्रवीण कुमार को भारी मतों से विजयी बनाये।



अजमेरा एस प्रवीण कुमार
इंदौर लोकसभा क्षेत्र से आपके अपने प्रत्याशी

लोकसभा प्रत्याशी अजमेरा एस प्रवीण कुमार के बारे में गुगल पर सर्च करें और उनके बारे में जानें, सोच समझकर सच्चाई देखें एवं अपने मत का उपयोग करें

: निवेदक :

मध्य प्रदेश घर निर्माण मंडल रहवासी संघ, एलआइजी गुरुद्वारा इंदौर मीडिया मंच के सभी प्रदेश और देश के पत्रकारगण अखिल भारतीय हिन्दू क्रांति पार्टी

संपादकीय

सत्ताधीशों के सारे पाप भी पुण्य

कानून धूर्तों के बनाए शब्दों के मायाजाल रुपी हथियार हैं, जो अपनों के पोषण और निरीहों के शोषण के काम आते हैं। वर्तमान परिदृश्य और संदर्भों में को देखते हुए यह परिभाषा मेरी अपनी अवश्य है। परंतु कानून की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। यह वर्तमान में भारत की चुनावी नौटंकी का हिस्सा बन चुके हैं। इसमें मोदी और उसकी भुखेरा जन पार्टी या उसका गिरोह सारे कानूनों का उल्लंघन करता है। जनता को चुनावकर्षण के लिये भाषणों में निम्न शब्दावली के साथ झूठी, कोरी बकवास व औचित्यहीन आश्वासन देता हुआ, सपनों के सब्जबाग दिखाते हुए, विपक्ष को गरियाता है। जब उसके विरुद्ध शिकायतें की जाती हैं। तब देश का उसका खरीदा हुआ मिडीया और उसको सर्वोच्च न्यायालय व चुनाव आयोग जो उसके बिठाए हुए पैदलों के जनता को भ्रमित कर मानसिक सांत्वना देने व भ्रम में उलझाने व समझाने के सरकारी संस्थान बन चुके हैं। शिकायत कर्ता को डराने, धमकाने और हतोत्साहित करने के साथ, हर सच की उपेक्षा करते हुये, जो अपना आकाओं के खिलाफ होते या जाते हैं, खारिज कर देते हैं। जबकि इसके विपरीत सत्ताधीश गिरोह के लोग विपक्षियों को डराने धमकाने और सच को छुपाने रोकने, शिकायत करते हैं, तो तत्काल में उनके विरुद्ध फ़ैसले उनके पक्ष में दे दिये जाते हैं। अर्थात् 'समर्थ को नहीं दोष गुसाई' यह तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लगभग 400 साल पहले लिख दिया था। वैसे भी कानूनों की व्याख्या शब्दों में नहीं सत्ता के छल, बल और पूजा पतियों के धन के हिसाब से सदा से होती चली आ रही है, सत्ता की जिसके पास लाठी, सत्ता की वही भैंस चराएगा, उसका घी, दूध, मक्खन भी वही खायेगा।

फिर सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए सारे न्यायाधीश, चुनाव आयोग के आयुक्त, वे सभी साधारण इंसान ही हैं। कोई देव पुरुष तो नहीं, जो मानवीय विकारों, यथा काम, क्रोध, मद, मोह, माया, यश आदि से घिरे बंधे हुए 3-13, 9-18 के चक्कर में फंसे हुए रहकर ही, सत्ताधीशों से संबंध रहते धन, बल, छल की बड़ी जुगाड़ और पहुंच से इस पद तक पहुंच पाते हैं तो स्वाभाविक है कि उन्हें अपने सत्ताधीश आकाओं के निर्देशों के पालन के साथ उनकी मान-सम्मान की रक्षा करना विवशता होती है। इसलिए सत्ताधीशों के सारे कुकर्मों में उनका पक्ष लेना, उन्हें निर्दोष साबित व सिद्ध करना उनकी सेवा की आवश्यकता होती है। अर्थात् बाद फिर वही पहुंच जाती है सारी नियम कानून चाहे वह चुनाव आयोग की हूं या सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया हो। सब में घोर पक्षपात किया जाता है। होता है। सारे नियम कानून कमजोर कड़ी कौन, पर पुलिस, प्रशासन, चुनाव आयोग, निर्दलीय छोटे दलों के उम्मीदवारों पर लादते घुमाते, चलाते, हडकाते, डराते, धमकाते हैं। बड़े दलों के प्रत्याशी 5-5 सौ सभा धार्मिक, सार्वजनिक बगीचों, सभाग्रहों, स्थलों पर करें। हर दिन हजारों लोगों का भंडारा करें। बड़ी बड़ी रैलियां निकालें। सौ-सौ वाहन चुनावी कार्य करें। उन्हें कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं। सारे पर्यवेक्षक, उनके प्रतिनिधि सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस प्रशासन सब मूकदर्शक बनकर देखते रहते हैं उनके चुनावी खर्च में सारे खर्चे नहीं जोड़े जाते जबकि दूसरी ओर छोटे दलों के या निर्दलीय उम्मीदवारों को हर कदम पर 2-4 घंटे प्रतिदिन इन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए निर्वाचन अधिकारी के पास चक्कर काटने पड़ते हैं और बैठाए रखा जाता है। ताकि छोटे दलों व प्रत्याशी अपने मतदाताओं के पास जाकर अपना परिचय दें वोट मांगने की जरूरत ही ना कर सके उसका सारा समय शासकीय निर्वाचन कार्यालय में आने जाने में बर्बाद हो जाए। इसके विपरीत सत्ताधीशा आकाओं के लिए कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, यहां तक की ईवी मशीनों को खोल कर उनसे निकले मतों की संख्या की बिना प्रथम विधानसभा स्तर की और दूसरी पूरी विधानसभाओं की लोकसभा के लिए हर चक्र की ऑफिस एक्सल शीट में योग और महायोग लगाए बिना भी बड़े आसानी से पुरी जालसाजी पूर्ण आत्म विश्वास के साथ करते हुए जब की मशीनें रात्रि 10:30 बजे तक खोली जाती रही, घोर हरामखोर, जालसाज जिलाधीश उप जिलाधीश ने पूरे देश भर में भाजपा की उम्मीदवारों को अपरान्ह 3:30- 4:00 बजे के बीच बनारस में मोदी को इंदौर में सुमित्रा महाजन को अपने जादुई अंदाज में लाखों वोट से जिता दिया था। यह कृत्य भी चुनाव की आदर्श आचार संहिता का पूर्णता: जालसाजी पूर्ण भारी अपराध होने के बावजूद भी सत्ताधीशों के सत्ता की शक्तियों के कारण पुण्य थे। अर्थात् चुनाव आयोग और उसकी सारी कार्यशैली, जो क्षेत्रीय स्तर पर, सरकार में बैठे सत्ताधीश द्वारा बैठाए गए जिलाधीश उप जिलाधीश द्वारा जो चुनाव आयोग का निर्वाचन अधिकारी होता है, के इशारे पर पूरी की पूरी नौटंकी की जाती है।

हर प्रकार के षड्यंत्र रचे, हर कदम ...

पेज 1 का शेष

टेलीविजन पर इसके आने के साथ ही देश के अंदर 40 करोड़ टीवी से लूटने के लिए पिछले 5 सालों में जनता से करीबन करीबन 40 करोड़ X रु. 5000 हर साल 2 लाख करोड़ लूटा गया। कभी डिस्क के साथ सेटअप बॉक्स रिमोट लगाने काटने जोड़ने सिंगनल ना आने। जबकि महीने का रु. 200 का औसतन शुल्क टाटा स्काई, रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन आदि ने लूटा वह भी 2400X40 करोड़ टीवी अर्थात् रु. 96000 करोड़ की लूट अलग से।

स्मार्ट सिटी के नाम पर हर शहर की सड़कों, भवनों कॉलेजियों को तोड़फोड़ कर 20 से 50% कमीशन पर अपनी ही पार्टी के लोगों को हजारों करोड़ के ठेके दिए गए। इस तरह से लोगों का जीना मुश्किल कर दिया गया। यही हाल राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों का भी हुआ। जहां पर 50 से 200 रु की डीपीआर बनाकर राष्ट्रीयकृत बैंको से हजारों करोड़ का कर्ज़ दिलवाकर मोटा पैसा सीधा पैसा हजम किया गया।

विपक्ष में रहते हुए 49% विदेशी निवेश पर पूरे देश में भौकने और हुआ हुआ करने वाले ये भुखेरा जन पार्टी ने आते ही न केवल फुटकर व्यवसाय में वरन् बैंकिंग, बीमा, संचार, समाचार पत्रों, टीवी प्रसारण में भी जनता को चूँँ दिशी बर्बादियों के लिये थोप दिया।

इन सब से भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने पूजा पतियों के फायदे के लिए देश में जीएसटी लागू कर दिया जीएसटी लागू करते समय 30 जून 2017 की रात्रि में देश की बर्बादी का जश्न मनाने संसद भवन में घंटा घड़ियाल बजाए गए। इस जीएसटी में बाहर से देखने को एक टेक्स था। परंतु यथार्थ में जीएसटी के 3 भाग थे पहला सेंट्रल जीएसटी दूसरा स्टेट जीएसटी तीसरा अंतर राज्यीय जीएसटी। इस बीएससी को लगाने से पहले उस सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी बस पूजा पतियों के चार्टर्ड बनाम करट अकाउंटेंट

की सलाह पर देश के छोटे व्यापारियों उद्योगों को को नष्ट करने, जो षड्यंत्र पूजा पतियों ने रचा था उस में उलझ कर लगभग 50 लाख से ज्यादा छोटा उद्योग दुकानदार, व्यापारियों ने मजबूरन उसके सजा के प्रावधानों के चलते कारोबार बंद कर दिया उससे भी 10 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। ज्यादा हल्ला मचाने पर लगभग 550 दिन में 600 से ज्यादा बदलाव जीएसटी में किए गए इससे लोग और उलझ कर व्यवसाय बंद करने के लिए मजबूर हुए। इसके विपरीत दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल बड़े उद्योगपतियों को मोटा फायदा होने लगा।

जिन सवर्णों की रोटी बोटी खाकर 40 साल में भेड़ियों का झुंड सत्ता तक पहुंचा पहुंचते ही हर जगह हर कदम उनकी बरबादियों की दास्तां लिखना शुरू कर दी। हल्ला मचा तो 10 रु का टुकड़ा डाल मुंह बंद कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने एट्रोसिटी एक्ट में संविधान के अनुकूल बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं की व्यवस्था दी।

तो इन हरामखोरों जालसाजों को वह भी नहीं पचा। शूकरों ने अध्यादेशों से कानून ही बदल दिया। और हिंदुओं को हिंदुओं में ही लड़ाने की व्यवस्था कर दी।

जिन हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा के लिए वोट दिया था। उल्टे ही उन पर अत्याचारों से उन्होंने मुंह फेर लिया।

कॉलोनी की कालोनियां हर शहर में हिंदुओं को डरा धमका कर और उनकी संपत्ति और मकानों पर कब्जे करने जो कि दिल्ली से लेकर देश के हर शहर में चल रही है इनमें उस पर कोई ध्यान कभी नहीं दिया। कहां मर गई आर एस एस कहां चले गए हिंदुओं के वोट हिंदुओं को डरा धमका कर लेने के बाद में भी क्या सुरक्षा मिली हिंदुओं को।

आपराधिक मानसिकता के मोदी और शाह ने पूरी भाजपा को रखैल की तरह उपयोग कर पुरी सरकार को अपने तरीके से नचाया, और देश के कानूनों का भारी दुरुपयोग किया।

भाजपा का घोषणा पत्र विश्लेषण

पेज 1 का शेष

एक तरफ से बेरोजगारी बढ़ेगी इससे 10 करोड़ छोटे-मोटे दुकानदार से लेकर रेहड़ी और फुटपाथ के सब्जी बेचने वाले तक सब बेरोजगार होने से उनके परिवार की 40 करोड़ लोग और बेरोजगार हो जाएंगे।

स्वभाविक है मोदी को वोट देने के साथ कटोरा खरीदने की व्यवस्था अवश्य रखें।

सन 2016 में अकेले इंदौर में 10000 से ज्यादा हाथठेले नगर निगम वालों ने और पूरे भारत में लगभग 50 लाख हाथ ठेले उन गरीबों के तोड़े।

जो उन हाथठेलों पर वे गरीब लोग सब्जी भाजी से लेकर छोटे-मोटे घरेलू सामान देश के लगभग 7600 नगरों के फुटपाथों और गली मोहल्ले में घूम घूम कर बिक्री कर के अपनी आजीविका पाल रहे थे। इससे करीब 50 लाख गरीब लोगों के साथ उनके ढाई करोड़ परिवार के सदस्य भुखमरी की कगार पर आ गये। मात्र पूंजी पतियों के बड़े शॉपिंग मॉल्स की बिक्री बढ़ाने, मोटा लाभ कमाने और जनता को लूटने के लिए उनके इशारे पर उन नगरों के पार्श्वों, महापौरों नगर निगम आयुक्त

पालिकाओं के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने जिन्हें मोटा धन इन शॉपिंग मॉल्स द्वारा बांट दिया गया था। के इशारे पर नगर पालिका निगमों के कर्मचारियों द्वारा जब्त किया जाकर तोड़ा गया। हाथठेलों जन्मी पहले भी होती थी। पर छोटा-मोटा दंड लगाकर छोड़ दिए जाते थे।

यह तांडव सबसे ज्यादा भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों के सरकारों के राज्यों में हुआ। बदले में वहां के भाजपा पार्श्वों, महापौरों, विधायकों, सांसदों के क्षेत्रों में ज्यादा हुआ।

मोदी के अंध भक्त यह सब कुछ जान कर भी भूल गए बदले में बेरोजगारों ने अपराधों का तांडव करना शुरू कर दिया।

सन 2016 में मोदी सरकार ने अपने आकाओं अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, वॉलमार्ट के शॉपिंग मॉल्स के की बिक्री बढ़ाने के लिए पहले पूरे देश में 50 लाख से ज्यादा को हाथठेलों को तोड़ा, फिर उनके लाभ के लिए नोट बंदी 8 नवंबर 16 को लागू कर दी गई। ताकि छोटे-मोटे लगभग एक करोड़ से ज्यादा किराना, खाद्य वस्तु विक्रेता, खाद्य वस्तु उत्पादक उद्योग जिसमें नमकीन मिठाइयां, छोटे लघु

उद्योग आदि में रोजगार पा रहे 10 करोड़ से ज्यादा लोग गार होने के साथ लगभग 50 लाख से ज्यादा लघु उद्योग दुकाने आदि नगदी के अभाव में बंद हो गए जिसका गुनाहगार पूर्णता: मोदी और उसके पूंजीपति 20-30 आका ही थे।

मोदी को यही चैन नहीं पड़ा, लगभग 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लेकर अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों और देसी कंपनियों के मोटे लाभ के लिए लादा गया। 1 जुलाई 2017 से बिना तैयारी के माल एवं सेवा कर अर्थात् जनता और छोटे व्यापारियों को मसक से इस तरह से मसला गया की उसके लागू होने के बाद 640 दिन गुजर जाने के बाद स्वयं जीएसटी कार्टिसिल जिसने 500 से ज्यादा कार्य दिवसों में लगभग 550 संशोधन कर दिए, से लेकर, पूरे देश के सभी राज्यों के विक्रय कर और केंद्र के कस्टम व एक्ससाइज विभागों के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों तक को वह मसक कर आज तक नहीं समझ में आया।

सारे देश के लगभग 50,000 से ज्यादा कर सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट तक नहीं समझ पाए। तो बेचारे 3 करोड़ से ज्यादा छोटे व्यवसायी, उद्योगपति, दुकानदार

स्थानांतरणों में हुई मोटी वसूली

मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही 15 साल से भूखे बैठे, सत्ता मिलते ही मंत्री संत्री टूट पड़े भूखे बंगालियों की तरह हर तरफ से पैसा इकट्ठा करने की प्रतियोगिता शुरू हुई मंत्रियों में, फिर उन्होंने कोई कानून कोई मानदंड कुछ नहीं, पैसा लाओ मनचाही पदस्थापना पाओ के स्थानांतरण उद्योग से कमाई करते समय पूर्णता: आंख मीच कर, दोनों हाथ से बटोरा।

लोक निर्माण विभाग में जिन अधिकारियों ने मोटा धन दिया उनके सारे पाप भूल कर मनचाही पदस्थापना दे दी गई इसके लिए उन्होंने कोई वरिष्ठ कोई कनिष्ठ नहीं देखा। वैसे तो उच्च न्यायालय के कहने के उपरांत भी पदोन्नतियां नहीं की गईं। मोटी धनराशि को वसूलने के लिए कनिष्ठों को प्रभारी बनाकर चुन चुन के सारे भ्रष्टों को बोली के हिसाब से पद बांटे गए। इंदौर के संभाग 1 में, बोली बढ़ती गई, पदस्थापना हुई, बोली बड़ी स्थानांतरण हुआ, रु 25 लाख खर्च कर अनिंद्र, 2 दिन बाद मंत्री को 35 मिले तो जायसवाल को बैठा दिया गया।

संभाग क्रमांक 2 में डेढ़ साल पूर्व पदस्थ प्रदीप सवसैना को मंत्री की मांग पूरी ना होने के कारण, स्थानांतरित कर दिया। दूसरी तरफ धार में बैठा बंसल जो नर्मदा घाटी से फर्जी पुनर्वास के काम में मोटा धन वसूल कर आया था पहले पैसे के दम पर धार संभाग में पदस्थापना ली। अधिक शिकायतें होने के कारण उसका स्थानांतरण वहां से गुना कर दिया गया। बंदे ने 25 लाख रुपए फेंक, अपना स्थानांतरण संभाग 2 में करवा लिया, वहां से कार्यपालन यंत्री को भोपाल कार्यालय में कर दिया गया। बाद में इसके विरुद्ध का य सक्सेना को उच्च न्यायालय से बच्चों की पढ़ाई के चलते स्थगन लेना पड़ा। रु25 लाख में घोर बदतमीज और भ्रष्ट अधीक्षण यंत्री जी एस मंडलोई को प्रभारी बनाकर पश्चिम परी क्षेत्र का मारी प्रभारी मुख्य अभियंता बना दिया गया वहीं दूसरी ओर 8 साल से बैठा अधीक्षण यंत्री के समकक्ष संयुक्त संचालक पीआईयू खरात इंदौर एडी पीआईयू कार्यालय में कुंडली मारे बैठा हुआ है।

विक्रेता आदि क्या खाक समझ पाएंगे।

इस चक्कर में लगभग 50 लाख से ज्यादा छोटे व्यवसायी बंद करने के लिए मजबूर हो गए।

अर्थात् अगले 5 साल में भेड़िया जानवर पार्टी इस देश में 50 करोड़ लोगों को बेरोजगार बनाकर कटोरा थमा कर चौराहे पर भीख मांगने के लिए छोड़ देने की तैयारी करके बैठी हुई है। उसे रोजगार से कोई मतलब नहीं। बदले में मैं इन भिखारियों को दो वक्त की रोटी खाने लायक रु. 75000/- साल देकर यूरोप की तरह सारा व्यवसाय 25-50 पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप देगी।

दूसरी तरफ रेलवे परिवहन, डॉक, भारत संचार निगम लिमिटेड, तेल कंपनियां, विद्युत मंडल, सड़कें, बैंकिंग, बीमा आदि अधिकांश सरकारी कंपनियां विभाग सब का निजीकरण हो जाएगा और वे सब लगभग 50% कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने संस्थानों से बाहर कर देंगे।

जिससे लगभग दो करोड़ लोग और बेरोजगार हो जाएंगे मोदी के अंध भक्तों को उसके घोषणा पत्र से समझ लेना चाहिए।

जनता से लूटा हुआ धन मंत्रियों और अधिकारियों तुम्हारे बाप की जागीर नहीं मध्यमवर्गीय को लूटो, वोटों के लिए अमीरों और गरीबों को लुटाओ

13 साल के बाद में भी सूचना के अधिकार में जानकारी नहीं और विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध कराते नहीं। खुले में मंचों से नेता जनता से मताकर्षण और चुनाव जीतने के लिए कर्ज माफी, मुफ्त का लैपटॉप, मोबाइल फोन, साइकिल व अन्य सामानों का लालच देकर चुनाव जीते जाते हैं क्या यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। आखिर यह यह धन मध्यमवर्गीयों से ही लूटा जाता है और बदले में उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ता है।

भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू हुए भले ही 70 साल गुजर गये हों। परंतु राष्ट्र में लोकतंत्र और शासन व्यवस्था परिपक्व नहीं हुई। यहां पर अभी तक आदिकालीन युग की जिसकी लाठी उसकी भैंस बली व्यवस्थाएं वर्तमान में भारत की शासन व्यवस्था में

चल रही है। अर्थात् सत्ताधीश और विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए खुले में धन और बल के दम पर जनता को लुभाने के लिए उन्हें लालच देकर जिस में किसानों को ऋणमाफी, युवाओं और छात्रों को जन धन से बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त का लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल फोन साइकिल आदि का लालच देकर सत्ता हथियाने का खेल पिछले 70 सालों से जबकि यह चुनावी आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन होता है। इस बार 25 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सामाजिक संगठन द्वारा 2011 में लगाई गई याचिका पर दिए गए निर्णय में स्पष्ट कहां और निर्णय लिया गया हर उम्मीदवार को उसके पुराने आपराधिक प्रकरणों जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर न्यायालय में लंबित प्रकरणों जिसमें

आरोप लगा दिए गए हो ना लगाये हो, जिन प्रकरणों में सजा हो गई हो सजा पूर्ण करने के बाद आदि सब की जानकारी आपको ना केवल उम्मीदवारी के फॉर्म में भरनी है, वरन चुनाव का मतदान होने से 48 घंटे पूर्व उन सभी प्रकरणों के बारे में आपको अखबार में विज्ञापन भी देना है। इसके विपरीत 25 सितंबर 2018 के बाद भारत के 5 राज्यों में जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मेघालय आदि में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए परंतु किसी किसी भी उम्मीदवार ने भाजपा-कांग्रेस व अन्य सभी राजनीतिक दलों व निर्दलीय ने इस संबंध में विज्ञापन समाचार पत्रों में ही नहीं छापा जो कि खुले रूप से सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अब मानना था इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सत्ता धीश और विपक्ष में

राष्ट्रीय स्तर की दल कांग्रेस ने कोई भी टिप्पणी और कार्यवाही नहीं की। साथ ही एक दूसरे की इस मामले में कोई भी आरोप भी नहीं लगाया गया क्योंकि दोनों ही दलों के प्रत्याशी अधिकांश आपराधिक श्रेणी के अनेकों प्रकरणों में लिप्त हैं। इसमें अनेको तो हत्याओं की गंभीर अपराध में सजा पूरी कर चुके हैं, या उनके ऊपर न्यायालयों में आरोप लगाए जा चुके हैं और प्रकरण हम दिखाए लंबित हैं, अधिकांश पर आपराधिक प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना में दर्ज हैं और प्रकरण से संबंधित कार्रवाई न्यायालयों में भी लंबित है इसमें मुख्यमंत्री से लेकर राजस्थान का उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट जो अपराधों में लिप्त होने के उपरांत भी ना केवल चुनाव लड़ा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले

चुका है। अर्थात् यह देश सभ्य लोगों की सत्ता का देश नहीं यह देश आदिमकालीन असभ्य अपराधियों की सत्ता का देश है। यहां उच्च पदों पर बैठे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यथार्थ में भारतीय प्रताड़ना सेवा के वो अधिकारी हैं, जो स्वयं घोर, बिकाऊ, गुलाम, जालसाज, चालबाज, सत्ता धीश नेताओं की रखैल और सफेदपोश अपराधी हैं। जो जिलों में जिलाधीश आयुक्त आदि के रूप में कार्यरत होते हैं। चुनाव आयोग के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में बैठकर, सत्ताधीश जालसाजिया संपन्न करते हुए चुनाव कार्यों को संपन्न करवाते हैं। निर्दलीय जो अपराधों में लिप्त होने के उपरांत भी ना केवल चुनाव लड़ा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले

से लेकर पार्टी के एबी फॉर्म को रद्द करने उसे निर्दलीय घोषित करने तक का कार्य करते हैं। जैसा कि 2014 में लोकसभा के चुनाव में इंदौर में पदस्थ जिलाधीश आकाश त्रिपाठी ने अजमेरा प्रवीण कुमार के साथ किया था। 4 अप्रैल 2014 को अजमेरा प्रवीण कुमार ने हिंदू महासभा का एबी फॉर्म लोकसभा प्रत्याशी के रूप में जमा कि या जिसे उस समय स्वीकार कर लिया गया परंतु 9 अप्रैल 2014 को अजमेरा प्रवीण कुमार का नाम बदलकर प्रवीण कुमार जैन कर दिया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा क ए बी फॉर्म जालसाजी पूर्ण तरीके से रद्द करते हुए उन्हें निर्दलीय घोषित कर दिया गया। जो इन हरामखोर जालसाजों की बदतमीजीयों का उत्कृष्ट प्रमाण था। निःसंदेह अखिल भारतीय हिंदू महासभा का बहुत बड़ा दल नहीं था।

मोदी को चुनाव जीता या तो भविष्य में चुनाव नौटंकी समाप्त तानाशाह मोदी संविधान बदल कर शासन करेगा जीवन पर्यंत

पड़ोसी देश में 18 मार्च 18 को पुतिन ने रूस में साम दाम दंड भेद के षडयंत्र से ही संविधान बदल कर हमेशा के लिए उसकी सत्ता हथिया कर आजीवन राष्ट्रपति बन गया। इसी प्रकार 22 मार्च 18 को चीन का जिन पिंग भी इसी तरह साम दाम दंड भेद और अपने विरुद्ध उठती हर आवाज को कुचल कर वहां का संविधान बदल आजीवन चीन का प्रधानमंत्री बन गया।

अब इन दोनों के बाद भारत और उसका मोदी है अगली बार सत्ता येन केन प्रकरणे हथिया कर वह भी संविधान बदल सभी अपने विरोधियों को नष्ट कर आजीवन भारत की सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। खुश होना चाहिए मोदी के अंध भक्तों को उनका यह मसूबा पूरा होते ही एक कम से कम 10 करोड़ लोगों से रोजगार छीनकर, इसमें देश के पांच करोड़ किसानों, 2 करोड़ फुटपाथ, हाथ ठेले, छोटे दुकानदारों, छोटे उद्योगों, आदि को बेरोजगार बनाकर, कटोरा थमा कर चौराहे पर खड़े होकर अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, वॉल मार्ट आई टी सी, हिन्दूस्तान लीवर के शॉपिंग मॉल के सामने दो वक्त की रोटी की याचना अपने परिवार के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि सन 2016 में इन शॉपिंग माल वालों का पेट भरने व बिजनेस बढ़ाने के लिए, अकेले इंदौर में ही नगर निगम कि भाजपा की गैंग ने

अमित शाह गांधीनगर से चुनाव जीतकर सत्ता में पहुंचा, और मोदी प्रधानमंत्री बना, तो दोनों मिलकर निश्चित ही संविधान बदल देंगे



फुटपाथों से लगभग साग सब्जी फल फ्रूट के 12000 से ज्यादा ठेले जब्त कर तोड़ दिए थे। और इस प्रकार लगभग 20 हजार लोगों को बेरोजगार बना दिया गया था यही हाल देशभर में लगभग 40 लाख ठेले तोड़कर लगभग 60 लाख लोगों को बेरोजगार बना दिया था। वैसे भी ओएनजीसी, बीएसएनएल, पोस्ट ऑफिस, सरकारी बैंको, बीमा कंपनियों व अन्य सरकारी उपक्रमों से चुनाव के बाद, जोकि मोदी सरकार के पहले लाभ में चल रहे थे। अपने पूंजीपति आकाओं के लाभ के चक्कर में हजारों करोड़ के घाटे में आ गए। लगभग 20 लाख कर्मचारी नौकरी से हटा दिया जाएंगे। तब समझ में आएगा की आपराधिक प्रवृत्ति के एक अनपढ़ व्यक्ति सत्ता में पहुंचने के बाद, किस प्रकार कानूनों का मखौल उड़ा कर देश की जनता

के हितों को बलाये ताक रखकर, करोड़ों लोगों को बेरोजगार बनाकर भूखा मारने के लिए छोड़ देता है और उनसे लूटे हुए पैसे से लाखों रुपए के कपड़े पहन कर, सरकारी पैसे से पूरा जहाज खरीद कर, उड़ान भरता है। विदेशों में मौज मस्ती करते हुए अपने कुकर्मों को छुपाने, जनधन के पैसे से हजारों करोड़ के झूठे विज्ञापन प्रसार माध्यमों में जारी कर, देश का पैसा बर्बाद करता है दूसरी तरफ देश की रिजर्व बैंक दूसरी बैंकों को दिवालिया बनाकर छुपाने के लिए उनका संविलियन करता है। इसके विपरीत वह पाखंडी जोर जोर से अपने झूठों को चिल्ला चिल्ला कर सच बता कर, जनता को डरा धमका कर राष्ट्रवाद का नशा पिला कर चुनाव जीतने के लिए नौटंकी करता रहता है विपक्ष को बदनाम

करने के लिए अनर्गल झूठे आरोपों की बारिश करता रहता है जब उससे सफल नहीं हो पाता तो सत्ता के मद में कानून का दुरुपयोग कर उन्हें परेशान करने के लिए मुकदमे लादता है। स्वाभाविक है, सत्ता में आने के बाद यह पाखंडी भी रूस और चीन की तरह भारत में भी संविधान बदल कर अमित शाह सांसद बनने व संसद में पहुंचने के बाद छोटे दलों के सांसदों को श्याम दाम दंड भेद से खरीदकर डरा धमकाकर संविधान बदल कर आने वाले भविष्य में मोदी को आजीवन प्रधानमंत्री बना देगा और चुनाव की व्यवस्था खत्म कर देगा। पूंजी पतियों की सेवाओं में सारा सरकारी तंत्र सारी बैंक समर्पित होकर किसानों की सारी भूमि हड़पी जाएगी सारे छोटे उद्योग, व्यवसाय दुकान समाप्त हो जाएगी जैसा कि नोटबंदी और जीएसटी से हुआ। चारों तरफ करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे, पेट भरने के लिए महिलाएं वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर होंगी। मोदी के अंध भक्तों को अपनी औकात पता चलेगी। वैसे तो नोटबंदी और जीएसटी में 2 महीने पूरा देश बेरोजगार बैठा रहा सारे उद्योग धंधे, 50 लाख से ज्यादा टुक, बंद हो चुके थे। भयावह बेरोजगारी चारों तरफ पूरे देश में तांडव कर रही थी। ये धूर्त पाखंडी विदेशों में मौज मस्ती कर रहे थे। शायद आधुनिक युग के कंस और रावण के प्रतिबिंब हैं।

हिंदूत्व पर समय माया का पुराना संघर्ष चुनाव सिर पर तो याद आया हिन्दुत्व

समय माया समाचार पत्र का प्रधान संपादक प्रवीण अजमेरा सन 2006 से कर्नल पुरोहित असीमानंद और साध्वी प्रज्ञा के लिए अकेले उनकी मुस्लिम परस्त और हिंदुओं को हिंदू आतंकवादी के कहने वाले कांग्रेसी द्वारा किए गए अत्याचार का विरोध करता रहा और उनके पक्ष में लगातार प्रकाशित करने वाला अकेला भारत का पत्रकार था।

तब तो उन ऊपर काफी उंगलियां उठाई जाती थी

इसके साथ ही भाजपा द्वारा स्वयं साध्वी प्रज्ञा को केंद्र के इशारे पर ना केवल विस्फोटों के मामले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता की हत्या के मामले में स्वयं भाजपा के शिवराज सरकार ने भी भारी प्रताड़ना मध्य प्रदेश की जेलों के साथ महाराष्ट्र की जेलों में भी दी गई।

मध्यप्रदेश में सन 2003 से 2018 तक भाजपा की सरकार रही उसने कभी उस साध्वी प्रज्ञा को बचाने की कोशिश तो दूर उल्टे ही उस पर जुल्म दाते रही दूसरी ओर यदि मोदी सच्चे हिंदूवादी प्रधानमंत्री थे तो उन्हें 2014 से 2018 तक सभी हिंदू राष्ट्र भक्तों को बचाने की और जेल से छुड़ाने की याद क्यों नहीं आई।

जब सिर पर लोकसभा चुनाव आ गए तो सारे अपराध खत्म कर सब को बरी कर चुनाव में खड़ा करवा दिया गया।

कितनी दोगली हरामखोर भेड़ियों की झुंड पार्टी है?

स्वयं हिंदू और और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता देख लें और समझ ले कि किस प्रकार मोदी और अमित शाह ने पूरी पार्टी के बड़े नेताओं को ब्लैकमेल कर गत में धकेल दिया।

स्वयं सत्ता पर काबिज होने के साथ जन धन के लगभग पांच लाख करोड़ केवल अपने स्वयं के प्रचार प्रसार पहनने ओड़ने सजने और सवरने, विदेशों में अय्याशी और मौज मस्ती करने में खर्च कर दिए।

घोर मक्कार, जालसाज गुजराती भेड़ियों अमित और नरेन्द्र किसी के सगे नहीं हो सकते पूरे देश को बहुराष्ट्रीय कंपनी और पूंजी पतियों के हवाले कर जो उनका इतिहास भी दोहरा रहा है जनता के लगभग 50 करोड़ लोगों को कटोरा थमा देंगे जीत जाने के बाद।

इंदौर लोकसभा सीट से प्रवीण अजमेरा समय माया समाचार पत्र के संपादक भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके 20 साल का इतिहास उनकी वेबसाइट www.samaymaya.com पर पढ़ देख और समझ सकते हैं।

जो अकेले ही पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निजीकरण के विरुद्ध जंग लड़ रहे हैं। छोटे दुकानदारों के व्यापार, व्यवसाय व किसानों की जमीनों को बचाने सत्ता से संघर्ष कर रहे हैं।

इंदौर की जनता ने इंदौर को सफाई में नंबर वन बनाया है

अब लोकसभा चुनाव में भी इंदौर की जनता राजनीति के दल-दल में आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों की सफाई कर

कर्मठ उच्च शिक्षित, ईमानदार, देश के और विश्व की जनता के हितों के लिए समर्पित पत्रकार अजमेरा एस प्रवीण कुमार को भारी बहुमतों से विजयी बनाएं

इंदौर की जनता से अपील

2019 के लोकसभा चुनाव में आप अपना अमूल्य मत आपके ही नगर के उच्च शिक्षित, कर्मठ पत्रकार जो साप्ताहिक समय माया समाचार पत्र के व www.samaymaya.com साइट के प्रधान संपादक हैं। पिछले 20 वर्षों से लगातार न केवल क्षेत्रीय प्रादेशिक, राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की जन, जल, जीव-जगत पर्यावरण के लिये लगातार सत्ता, पूंजीपतियों से आमजन, गरीबों, मजदूरों, किसानों के हित में संघर्ष कर रहे हैं। जिसकी सत्यता आप www.samaymaya.com की साइट पर देख सकते हैं।

निवेदन है अपने समाज, राष्ट्र व विश्व के सुखद, समृद्ध, शक्तिशाली शांतिपूर्ण भविष्य के लिए अपना अमूल्य वोट ट्रैक्टर चलाता किसान वाला बटन दबाकर

अजमेरा एस प्रवीण कुमार को भारी मतों से विजयी बनाएं।



चुनाव चिन्ह



अजमेरा एस प्रवीण कुमार
इंदौर लोकसभा क्षेत्र से आपके अपने प्रत्याशी

लोकसभा प्रत्याशी अजमेरा एस प्रवीण कुमार के बारे में गूगल पर सर्च करें और उनके बारे में जानें, सोच समझकर सच्चाई देखें एवं अपने मत का उपयोग करें

: सौजन्य से :

मप्र गृह निर्माण मंडल रहवासी संघ, एलआइजी गुरुद्वारा इंदौर

मीडिया मंच के सभी प्रदेश और देश के पत्रकारगण

अखिल भारतीय हिन्द क्रान्ति पार्टी

समस्त हाथ ठेला व्यापारी संघ

इंदौर की जनता ने इंदौर को सफाई में नंबर वन बनाया है

अब लोकसभा चुनाव में भी इंदौर की जनता राजनीति के दल-दल में आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों की सफाई कर

कर्मठ उच्च शिक्षित, ईमानदार, देश के और विश्व की जनता के हितों के लिए समर्पित पत्रकार अजमेरा एस प्रवीण कुमार को भारी बहुमतों से विजयी बनाएं

इंदौर की जनता से अपील

2019 के लोकसभा चुनाव में आप अपना अमूल्य मत आपके ही नगर के उच्च शिक्षित, कर्मठ पत्रकार जो साप्ताहिक समय माया समाचार पत्र के व www.samaymaya.com साइट के प्रधान संपादक है। पिछले 20 वर्षों से लगातार न केवल क्षेत्रीय प्रादेशिक, राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की जन, जल, जीव-जगत पर्यावरण के लिये लगातार सत्ता, पूंजीपतियों से आमजन, गरीबों, मजदूरों, किसानों के हित में संघर्ष कर रहे हैं। जिसकी सत्यता आप www.samaymaya.com की साइट पर देख सकते हैं।

निवेदन है अपने समाज, राष्ट्र व विश्व के सुखद, समृद्ध, शक्तिशाली शांतिपूर्ण भविष्य के लिए अपना अमूल्य वोट ट्रेक्टर चलाता किसान वाला बटन दबाकर

अजमेरा एस प्रवीण कुमार
को भारी मतों से विजयी बनाएं।



चुनाव चिन्ह



अजमेरा एस प्रवीण कुमार
इंदौर लोकसभा क्षेत्र से आपके अपने प्रत्याशी

लोकसभा प्रत्याशी अजमेरा एस प्रवीण कुमार के बारे में गूगल पर सर्च करें और उनके बारे में जानें, सोच समझकर सच्चाई देखें एवं अपने मत का उपयोग करें

: सौजन्य से :

मप्र गृह निर्माण मंडल रहवासी संघ, एलआइजी गुरुद्वारा इंदौर

मीडिया मंच के सभी प्रदेश और देश के पत्रकारगण

अखिल भारतीय हिन्द क्रान्ति पार्टी

समस्त हाथ ठेला व्यापारी संघ

हरामखोर, जालसाज गिद्धों गूगल, याहू, माइक्रोसाफ्ट अपनी मौत का सामान इकट्ठा मत करो

गूगल, याहू, माइक्रोसाफ्ट, फेसबुक, युट्यूब, व्हाट्सप, ट्विटर, अपनी औकात में रहना सीखो वरना तुम और तुम्हारी सारी फौज कहां पैदा हुई थी। कहां खत्म हो गई मालूम भी नहीं पड़ेगा। तुम्हारे ब्राउज़र को सेवाओं का उपयोग करने वालों 400 करोड़ लोगों को इतना परेशान मत करो कि उनकी बहुआएँ तुम, तुम्हारे मालिक और तुम्हारे साथ में काम करने वालों को कुत्ते की मौत मरने की भगवान से दुआएँ मांगने लगे तुम संकर प्रजाति के कमीनों तुम्हारी रगरग में अमेरिकियों जो कमीनापन भरा हुआ है। मौत के आंगन में बैठकर तुम्हें अक्ल नहीं आती और तुम जनता को उपयोग करने वालों को दुनिया भर में जिस तरीके से नोचते कचोटते और समय को बर्बाद करते हो सूअर की औलादों अपनी मौत का सामान उन की बहुआ से मत इकट्ठा करो। तुम्हारा पैसा तुम्हारी कब्र में साथ नहीं जाएगा कुत्ते की मौत मरोगे।

निःसंदेह मैं तुम्हें गालियां नहीं देना चाहता पर मेरी गालियों का धनात्मक रूप में उपयोग करें तो शायद आप आपकी कंपनी वर्षों तक दुनिया पर राज कर सकती है। परंतु आपकी बदतमीजीया सिर से ऊपर बहने लगी और आमजन इतना परेशान व समय बर्बाद करने लगी कि तुम्हें मैं अनावश्यक सचेत करते हुए गालियों के माध्यम से जागृत कर यह प्यारा संदेश देना चाहता हूँ। कि तुम लोगों का दिल जीत कर देवता बन सकते हो और परेशान कर दानव और अब तुमने दानवीय हदे भी पार कर ली।

यूरोप में उददुत पर उपभोक्ताओं को उसकी सेवाओं का उपयोग करने, विवश करने, डांटा चुराने और बेचने, दूसरी अन्य बदतमीजीयो के कारण ब्रिटेन ने रु. 36000 करोड़ का जुर्माना ठोका है।

बेशक भारत की सरकार मैं बैठे मंत्रियों से लेकर उनके मंत्रालयों मैं बैठे घोर गिद्धों भारतीय प्रताडणा सेवा अधिकारियों की भ्रष्ट फौज ने सैकड़ों करोड़ रुपए गूगल से हजम कर पूरी सरकार के हर मंत्रालय का डाटा जिसमे जनता का महत्वपूर्ण आधार कार्ड का डाटा भी उददुत के भारतीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुंदर पिचाई के माध्यम से गिरवी कर दिया है और वह उससे सेकड़ो करोड़ रुपए प्रति दिन की कमाई कर रहा है। उददुत नहीं सुंदर पिचाई को



चीनी तुम्हारी सारी दादागिरी, बदतमीजीयों व कमीनेपन का तैयार हैं, जवाब देने

इसीलिए मोटे वेतन पर अपने यहां उसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया।

इन बदतमीजीयों का जवाब देने के लिए चीन छटपटा रहा है। और वह तैयारी कर रहा है कि इन कं. को हर तरीके से नेस्तनाबूद कर के कंप्यूटर सांफ्टवेयर संचार तकनीकी पर पूर्ण कब्जा जमा कर इन्हे सदा के लिए अस्तित्व खत्म कर दे। इनका जनता के मोबाइलों, लैपटॉप और कंप्यूटर से डाटा चुराना, उनकी अपने उपकरणों से उनकी हर गतिविधि बातचीत पर नजर रख सारी जानकारियों को इकट्ठा कर देसी विदेशी दुनिया की सैकड़ों व्यावसायिक कंपनियों, जालसाजों, हैकरों सरकारों खुफिया एजेंसियों को उपलब्ध करवा कर प्रतिदिन हजारों करोड़ बटोरना, अनावश्यक मोबाइल खोलते ही विज्ञापन का ढेर दिखाना व्यवसाय करने के लिए हर उपयोगकर्ता को परेशान करना उसे कार्य न करने देना जैसी बदतमीजीयो से से परेशान दुनिया के 400 करोड़ उपभोक्ता हर पल हर क्षण उसकी आत्मा से निकलने वाली आह और बहुआएँ इनकी मौत की कामना करती हैं। यह बर्बादी चीन की विश्व पर नियंत्रण व साम्राज्य की

कामना को सफल बनाएगा।

वह जल्दी इन परेशान करने की नियत से दुनिया की जनता के सामने, इनके कर्मों से आसानी से यह सिद्ध करने में सफल रहेगा कि दुनिया भर की नस्लों की संकर प्रजाति के अमेरिकियों तुम कहीं से भी विश्वास के योग्य नहीं हो।

पृथ्वी पर स्थाई केबल प्राकृतिक क्रियाएँ ही हैं जो सहस्रों वर्षों से मौसम के अपने प्राकृतिक नियमों के अनुकूल चल रही हैं। आपका इंटरनेट और उससे चलने वाली सारी गतिविधियाँ अप्राकृतिक और आभासी हैं। जो किसी भी क्षण और पल में किसी भी दैहिक और देविक आपदा में नष्ट होकर बिखर जाएंगे। तब क्या होगा? इसी आभासी दुनिया के नष्ट होते ही प्रकृति के आंगन में मानव की यह आधुनिकता नष्ट हो कर पुनः अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौट आएगा यह प्रकृति का लाखों वर्ष पुराना अपना नियम और अपनी प्रकृति है। यह भारत के अनादि ग्रंथ ऋग्वेद में वर्णित है। प्रकृति की प्रकृति है कि वह प्रकृति के निकट रहे। जिसे लाखों वर्षों से मानव ने झुठलाने की अनवरत कोशिश की पर वह लौटकर उसी की शरण

में आ गया। आखिर संकर प्रजाति के अमेरिका में क्यों सबसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। सबसे ज्यादा ज्यादा तूफान आते हैं। बर्फ गिरती है। ज्वालामुखी फटते हैं। जिसमें लाखों लोगों को जीते जी परेशान होना पड़ता है। यहां वहाँ भागना पड़ता है। उसके पीछे मात्र कारण है तो चंद लोगों का की कंपनियों का घोर स्वार्थी मक्कार होना अनावश्यक आतंक फैला कर हथियार बेचना दवाइयाँ बैचना ही सबसे बड़े मुख्य कारण हैं। प्रकृति का नियम है कि आप अगर किसी को आंसू दोगे तो आपको भी आंसू ही मिलेंगे इसलिए माइक्रोसाफ्ट गूगल व अन्य सभी ऐप बनाने वाली कंपनियां जो लोगों के उपकरणों में घुसकर उनकी सारी जानकारियां चुराती हैं बैचती हैं उन्हें परेशान करती हैं। यथार्थ मैं अपनी मौत का सामान इकट्ठा करती हैं। जो किसी भी दिन चुपके से किसी भी बहाने आकर सभी को ले जाने वाली है।

प्रकृति का नियम है की हर चीज समय के अनुकूल अपनी उच्चता पर पहुंचती है। और निश्चित समय के उपरांत वह घड़ी के कांटो की तरह रसातल में समा जाती है। वही हाल आप सबका भी शीघ्र होने वाला है संभल जाओ अपने उपभोक्ताओं का दिल जीत कर इस दुनिया में देवताओं की तरह पूजे जाओ या हैरान परेशान करके दानवों की श्रेणी में जाकर करोड़ों लोगों की लोगों की हर पल गालियां खाकर कुत्ते की मौत प्राप्त करो। तुम्हारा नाम सुनने से भी लोगों को नफरत होने लगे।

यह याद रखना तुम से पहले लाखों सालों में लाखों करोड़ तुमसे श्रेष्ठ धनी और बुद्धिजीवी आकर खाली हाथ पसारे चले गए हैं। तुम्हारा भी तुम जानते हो शीघ्र प्रकृति यही हथ्र करने वाली है आप समझें मैं तो आप की बदतमीजी से दूसरों की तरह कोई ना कोई विकल्प ढूँढ ही लूंगा अपने काम करने के लिए और जनकल्याण की अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए क्योंकि मैं जानता हूँ मैं छोटा सा तिनका हूँ और मेरी व जनता की भी मृत्यु निश्चित है धरती की अपनी यात्रा में अपने अत्यंत अल्प साधनों से अधिकतम प्रभु या प्रकृति के चरणों में रहकर जल जलवायु जनता जंगल और जानवरों का अधिकतम कल्याण कर सकूँ या सकें। आप सहयोगी बनेंगे या राक्षस बन कर तकलीफ देंगे। यह आपका अपना निर्णय होगा।

विदेशों में हजारों करोड़ डॉलर जुर्माने का भुगतान किया

उपयोगकर्ता के डाटा से फेसबुक डाल रहा डकैती

फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग ने दुनिया के लगभग 200 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ताओं का हर वर्ष सारा डाटा दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेच कर, उनकी व्यक्तिगत गोपनीयता भंग कर, फर्जी फ्रेंड लिस्ट बढ़ाने के लिए, खास लोगों के लिए चुनावों में फुल टीम के साथ करोड़ों खातों में झूठी प्रशंसा लगातार भिजवाई गई, इससे लाखों करोड़ रु साल की कमाई की। गैर मुस्लिम लड़कियों को लव जिहाद में फसाया, और गैर मुस्लिम समाज की, बदनामी व बर्बादी की। जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू लड़कियां व शादीशुदा फेसबुक के माध्यम से फसाई गई। आईएसआईएस के लिए मुस्लिम

सावधानी से संभलकर उपयोग करें उपयोगकर्ता सभी सोशल साइटों का यहां कुछ भी मुफ्त नहीं

लड़कों की पूरी दुनिया से भर्ती करने के साथ, उपयोगकर्ताओं की बातचीत, आदि का जानकारियों का भी खुल कर दुरुपयोग किया गया और कमाई की गई। अमेरिका और ब्रिटेन की संसद ने ना केवल फेसबुक वरन सभी ऐसे

दुष्कृत्यों के लिए गूगल की भी पेशी करवा कर सैकड़ों करोड़ डॉलर का दंड केवल उपयोगकर्ताओं की जानकारी को बेचने के लिए लगाया। जबकि उसके अन्य दूसरे पापों पर मोटा धन हजमकर उसे छोड़ दिया



गया जबकि ऐसे जाल साज हरामखोर को 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को परेशान करने उनकी

विपरीत क्योंकि स्वयं मोदी ने ही पिछले 6 सालों में फेसबुक गूगल ट्विटर इंस्टाग्राम आदि पर सन 2013 से अपने पुंजीपति मित्रों से करोड़ों डॉलर लेकर व बांटकर हिंदुओं में एक तरफ भय फैलाकर, तो दूसरी तरफ झूठी तारीफें और वादों के दम पर देश के 30 करोड़ से ज्यादा फेसबुक उपभोक्ताओं को प्रमित कर 2014 का चुनाव जीत लिया था अभी भी यह कहानी चल रही है। जब स्वयं मोदी ही उसका भक्त बन कर उसके प्रसाद

का उपयोग करेगा तो स्वाभाविक है। फेसबुक की मालिक जुकर बर्ग को जनता का डेटा बेच कर गोपनीयता भंग करने में कोई सजा भारत में कैसे दी जा सकती है। फेसबुक ट्विटर गूगल इंस्टाग्राम व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को भारत में तो कोई राहत मिलेगी नहीं मिलेगी उनका डाटा केवल यह कंपनियां वरन स्वयं शासकीय कार्यालयों, बैंको, बीमा कंपनी, आधार कार्ड बनाने वाले सेवा प्रदाता कंपनियों, राशन की दुकानों, मोबाइल कंपनी में बैठे, मां के कर्मचारी अधिकारी स्वयं ही बेचकर मोटी कमाई करते रहते हैं। सरकार स्वयं जानती है। इसलिए जनता को अपनी सुरक्षा अपने हाथ ही करनी होगी।

जानकारियां नीलाम करने के आरोप में आजन्म कारावास की सजा दी जानी चाहिए थी। भारत में इसके

सरकारी सूत्र सेवा की बसों का मालिकाना हक निजी के पास

बैंक ऋण से सूत्र सेवा की बसों में अनुदान की राशि हड़पी

जालसाजी पूर्ण तरीके से भाजपा के नेताओं और उनके रिश्तेदारों नाम से बैंक ऋण से खरीदी गई

इंदौर में आईसीटीसीएल जिसे जवाहरलाल नेहरू पुनर्संरचना शहरीय व ग्रामीण विकास निधि से धन मिला। इसमें अटल सिटी बस सर्विस चलाई जा रही है। जिसमें बीआरटीएस का निर्माण हुआ इस बीआरटीएस में सन 2006 से 2014 तक इंदौर की 11.5 किलोमीटर निर्माण पर रु. 1150 करोड़ खर्च किया गया। अर्थात काम मात्र दो ढाई सौ करोड़ से ज्यादा का नहीं हुआ और करीब 900 करोड़ बंदरबांट में हजम कर लिया गया। यह फोटो सूत्रसेवा बस का है।

दूसरी तरफ एआईसीटीएसएल की सारी बसें ठेकेदारों की हैं। जबकि जेएनआर यूएम का केन्द्र का 50% पैसा और 50% मप्र सरकार में 25% निगम को लगाना था।

उस की अपेक्षा भाजपा नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को खास लोगों के नाम से बसें खरीद कर 50% अनुदान में मिला था। वो हजम कर लिया गया। बाकी बैंक ऋण से खरीद कर बसें लगा दी गई। अभी वर्तमान में यह बताएं सूत्र सेवा के नाम से केंद्र सरकार के पैसे से खरीदी गई परंतु इसमें भी यही शर्त थी। जबकि यह बसें भी सारी महापौर मालिनी गौड़ व अन्य नेताओं के रिश्तेदारों के नाम से खरीदी गई।

सरकारी धन की बंदरबांट कर ली गई इन बसों पर सूत्र सेवा का मध्य प्रदेश सरकार का मोनो लगा हुआ है और बस पर charteredbus.in का नाम लिखा हुआ है सवाल यह उठता है कि आखिर यह बसें किसकी हैं किसके आधिपत्य में चल रही हैं।



इसकी गवर्निंग बॉडी में इंदौर का आरटीओ कमिश्नर कलेक्टर महापौर है और पूरे कारोबार को संदीप सोनी नाम का एडीएम देख रहा है जो भारी बंदर बांट कर रहा है। साथ ही सारे कर्मचारियों को अधिकांश तकनीकी कर्मचारियों जिसमें ड्राइवर कंडक्टर तकनीशियन सबको ठेके में 8 रु.

10000 से ज्यादा नहीं मिल रहा। सब ठेकेदारी में नौकरी कर रहे हैं। आम सड़क किराए से यह बसें दुगना किराया वसूल करती हैं। समय भी आम बसों की तरह यहां से भोपाल का लगभग 4 घंटे लेती हैं और रु. 150 की जगह रु. 350/- किराया लेते हैं यह हाल यहां से चलने वाली हर बस का

है। सर्वोच्च न्यायालय के बार बार कहने के बाद मध्यप्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने अपनी बस सेवायें शुरू नहीं की।

परंतु इन हरामखोर शिवराज सिंह चौहान एंड कंपनी ने इन बसों को अपने नेताओं के रिश्तेदारों के नाम से उठावा कर इस प्रकार का यह फर्जी सरकारी संगठन खड़ा कर लूटपाट की जा रही है पिछले 12-13 सालों से। यह भी लगभग पूरे प्रदेश का रु. 25000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है सन 2006 से जांच करवाई जाने के बाद इसकी जांच भी खोलकर सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों और नेताओं को मुकदमे लाद और अपराध सिद्ध कर जेल में डाल के सड़या जाना चाहिए।

इन हरामखोरों से सूचना के अधिकार में बार बार पत्र देने के बाद भी जानकारी नहीं दी। ना यह बताया नहीं इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ? कौन-कौन डायरेक्टर है? पूंजी निवेशक, कार्यक्षेत्र, इसका प्राप्केटस क्या है।

क्योंकि पूरा खेल ऊपर के ऊपर हजम करने का चल रहा है। यही हाल मुख्यमंत्री शिवराज के खास पर्सल टूर कंपनी को भोपाल के सिटी बसों और भोपाल से चलने वाली बसों के मामले में की गई यहां पर भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यह गोरखधंधा सरकारी धन से खेल से खेला जा रहा है।

ग्वालियर जबलपुर में भी यहां के स्थानीय अधिकारियों और नेताओं के माध्यम से चल रहा है।

इ-टेंडरिंग की जांच में एस टी एफ के साथ बाहरी सायबर अपराध एजेंसी को भी करें शामिल

इ-टेंडरिंग में जांच जो अधिकारी जांच कर रहे हैं। उनसे अलग STF को बाहरी एजेंसी को साथ लेकर जांच करनी चाहिये।

वह भी अभी तक जिन ठेकेदारों ने उस ई टेंडरिंग की टेंपरिंग का लाभ उठाया। उन सब की भी जांच होनी चाहिए।

मोटे मोटे सैकड़ों से हजारों करोड़ के टेंडर लिए जिसमें नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जल संसाधन, इसका निगम, जो पीआईयू बना है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल निगम, लोक निर्माण विभाग, इस की शाखाओं में परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सेतु, म प्र सड़क डकैती विकास निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग, मप्र गृह निर्माण

मंडल, मप्र औद्योगिक केंद्र विकास निगम, प्रदेश के 7-8 नगर निगम और सारी पालिकायें, प्रदेश के विकास प्राधिकरण, मप्र विद्युत मंडल की 5 कंपनियों, आदिम जाति कल्याण विभाग, आदि विभागों अपनी भेड़ियों झुंड पार्टी के नेताओं उनके खास लोगों, फर्मों, कंपनियों को ठेके देने, दूसरे प्रतियोगी ठेकेदारों को कम दरों के बाद भी जालसाजियों से पिछले 15 वर्षों के विशेष तौर पर सिंहस्थ के ठेकों की लूटपाट और जालसाजियों की जांच होनी चाहिये। सभी विभागों के P.S. EnC, CE, SE & EE तक शामिल हैं। लपेटे में आयेंगे।

सिंहस्थ में तो PWD, के PIU, B&R, RDC, Bridge, सिंहस्थ संभाग,

E&M, सभी में, PHE में 300 करोड़ से ज्यादा की खरीद में इ-टेंडरिंग ने भ्रष्टाचार के आयाम स्थापित किये।

WRD, UDA, UMC, MP DPR, MP Health, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, महिला बाल विकास, पंचायत आदि सभी में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार का खेल हुआ। इसीलिए उज्जैन के किसी भी विभाग में बैठे सभी डकैतों ने RTI में कोई जानकारी नहीं दी।

अकेले उज्जैन में सिंहस्थ में रु 10 हजार करोड़ से ज्यादा भ्रष्टाचार में हजम किए गए।

जो सिंहस्थ का कार्य सन 2010 से चल रहा था। लगभग रु. 1 हजार करोड़ तो इस लूटपाट

से केन्द्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचा। मु. म. नाथ को चाहिए कि इनकी सच्चाई जनता के सामने लाकर भाजपा के, और सभी विभागों के दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। मामा के साले दिलीप बिल्डकान जो 13-14 सालों में लाखों के निवेश से रु20 हजार करोड़ की कंपनियों का मालिक कैसे बन गया। लोनिवि के 90% ठेकों में पत्थर, गिट्टी, रेत मुरम की रायल्टी हर ठेके की DPR के हिसाब से चुकाने की अपेक्षा बंदरबांट में हजम कर ली गई। उसकी साइटों पर कितने सरकारी खनन, लोनिवि के कर्मियों, मजदूरों की हत्या और मौत की भी जांच की जानी चाहिये। इ टेंडरिंग का शिबू का खास खिलाड़ी है।

रिजर्व बैंक को जागीर मान की चहुं दिशी बर्बादी

पेज 1 का शेष

नोटबंदी के सारे दुष्कृत्यों को करने के लिए उसने सबसे पहले उसने तत्कालीन रिजर्व बैंक के गवर्नर राजन को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। जब उसने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया तो उसे हटा दिया गया और अंबानी के रिश्तेदार उर्जित पटेल को जो कि भारतीय नागरिक भी नहीं था कीन्याई नागरिक होने के उपरांत भी उसे बैंक का गवर्नर बना दिया गया।

ताकि उसकी नोटबंदी के षडयंत्रों दुष्कर्मों को पूरा करने लाखों करोड़ के नोट छाप कर चुपचाप बांटने और हजम करने में कोई परेशानी न हो। अंबानी के यहां शादी में पूरे दस 12 मंजिल के घर को 2000 के नोटों से सजाने में आखिर यह सारी करंसी कहां से आई थी। जिसकी फोटो पूरे देश में व्हाट्सएप पर वायरल होते रहे। क्या यह जीजा को गवर्नर बनाने का पारिश्रमिक के बदले में प्राप्त गोरा धन था।

नोटबंदी के अंतर्गत मोदी ने स्वयं मंचों से स्वीकार किया, नोटबंदी की कार्यवाही और नोट छापने की प्रक्रिया मार्च 2016 से शुरू कर दी गई थी। अर्थात मार्च 2016 में रु 500 और रु 2000 के नोट छापने लगे थे। जबकि नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को की गई। परंतु रु 2000 के नोटों के बंडलों के साथ जुलाई 2016 में ही अनेकों भाजपा नेताओं के फोटो व्हाट्सएप पर भारी मात्रा में प्रसारित किए जा रहे थे। यह फोटो स्पष्ट कर रहे थे सत्ता धीश भुखेरा जन पार्टी किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जो लोग चलन में आए भी नहीं थे उन नोटों से उनके लोग खेल रहे थे।

रिजर्व बैंक में उसके कथनों के अनुसार 15.50 लाख करोड़ के नोट रु 500 और 1000 के चलन में थे। जिसके 60% नोट उसके पास लौट आए। और उसने 97.5% नोटों को बदल दिया है। प्रश्न यह उठता है की 37.5% नोट उसने अधिक कैसे बदल दिए। फिर सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर आखिर बार-बार रिजर्व बैंक क्यों टालता रहता है। जवाब देने की अपेक्षा उसमें उल्टे सीधे तर्क की दलीलें दी जाती हैं। फिर अपने पूंजीपति आकाओं के ऋणों को माफ करने और उससे डूबती हुई बैंकों को बचाने के लिए उसने रिजर्व बैंक के 36 लाख करोड़ के आरक्षित धन को बैंकों को देने के लिए कहा तो तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल ने भी इतने सारे कांडों के बाद देने से मना कर दिया। और दबाव बनाने पर उसने भी इस्तीफा देकर गवर्नर के पद का त्याग कर दिया।

इसलिए वित्त मंत्रालय के घोर भ्रष्ट और जालसाज शशिकांत को जिस पर पहले ही अनेकों भ्रष्टाचार और जालसाजी के आरोप थे। रिजर्व बैंक के अधिकारियों के विरोध के बावजूद भी उसे गवर्नर बना दिया गया।

रिजर्व बैंक का चोरी छुपे 268 टन सोना गिरवी कर दिया गया, घोर भ्रष्ट और जाल साज शशीकांत को गवर्नर बनाने के बाद, बैंकों की डूबत के लिए 3-3 लाख करोड़ की 3 किस्ते जारी कर दी गई, जो अपने पूंजीपति बापों को दिया था।

3 अप्रैल को अमेरिका से 24 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा रु. 18200 करोड़ में किया चुरकट मोदी देश का धन बाप की जागीर नहीं

जब 10 मार्च को आचार संहिता लगा दी गई। तो आपने मार्च के अंत में सौदा कैसे और क्यों किया? जाते जाते भी अपने बाप अंबानी के लिए मोटी फायदे का सौदा करवाने की हरकत से बाज नहीं आए।

दूसरी तरफ रफाल की तरह यह कबाड़ा भी अमेरिका के लिए समय बाधित अनुपयुक्त हो गया होगा। अमेरिका, फ्रांस जर्मनी ब्रिटेन कोई भी देश अपनी तात्कालिक अनुसंधान से तैयार युद्ध सामग्री चाहे व विमान हो, मिसाइल, टैंक, तोप, राडार, आदि दूसरे देश को कभी नहीं बेचता। यह सारे देश वहीं युद्ध सामग्री बेचते हैं। जो उनके लिए अनुपयोगी, समय बाधित व बेकार हो चुकी होती है।

फिर यह सौदा करना, आपकी मजबूरी इसलिए बन गया था ताकि अमेरिका आपके बालाकोट के सच को दुनिया को ना बताएं उसके बारे में चुप रहे कि आपकी वायु सेना ने कोई भी F16 नहीं गिराया 14 फरवरी को की गई फर्जी एयर स्ट्राइक के बारे में दुनिया को अमेरिका सच नहीं बताएं और चुनाव जीतने का आप का यह षडयंत्र नाकामयाब ना हो जाए। ज्यादा हल्ला नहीं मचे। इसलिए जाते जाते आपने अमेरिका का मुंह बंद करने के लिए यह 1995-8 का बना हुआ 20 साल

पुराना कबाड़ा खरीदा।

समुद्र में पनडुब्बी को डुबाने में सक्षम बताने वाले हेलीकॉप्टर रोमियो के बारे में आपने यह नहीं बताया की वह कितने घंटे की, कितनी लंबी उड़ान भर सकता है? समुद्र में पनडुब्बी की खोज करने में उसके अंदर समुद्र के अंदर 3 से 5 किमी गहराई में पनडुब्बी खोजने में, कौन सी सेंसर राडार लगे हुए हैं जो समुद्र में जाकर पनडुब्बी पर प्रहार कर के डुबो सकेगा। यदि 500 किलोमीटर दूर जाकर समुद्र में पनडुब्बी खोजेगा, और फोड़ेगा। तो क्या उसकी 5 से 6 घंटे की उड़ान भरने की क्षमता है। जो बिल्कुल असंभव है।

यदि बीच समुद्र से उड़ान भर खोजने भी गया, तो कितने विमान वाहक युद्धक जहाज है आपके पास।

निसंदेह महा झूठे, घोर मक्कार, नौटंकीबाज मोदी, मकड़ी की तरह जाला बनाकर दूसरों को फसाने की कोशिश में, तुम हर झूठ को जोर से चिल्लाकर बोलकर सच सिद्ध करने की कोशिश करते हो। और अंत में झूठ के जाल में फस जाते हो। मोदी चमड़ी के गुजराती घोर बेशर्म, झूठे मोदी जीवन के अंतिम पायदान पर देश की जनता को कब तक और कितना ठगोगे।

मेरा चुनावी घोषणा पत्र

1. देश के सभी एंड्रॉयड फोन पर 12 साल के बच्चों तक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए नई एप्लीकेशन की व्यवस्था के साथ सारी उत्पादक कंपनियों को फोन में ही 12 साल की उम्र से कम बच्चे के फोन छूते ही स्वमेव काला हो जाए की व्यवस्था करने के लिए कहा जाएगा। ताकि बच्चों का बचपन सुरक्षित रखा व मजबूत बनाया जा सके।

2. देश में गूगल का और भारत में जनता के डाटा को संग्रहित करने के लिए सरवर का विकल्प खोज, अमेरिका पर निर्भरता पूर्णता खत्म की जाएगी। ताकि देश की जनता के साथ होने वाली खातों से चोरी लूट डकैती को रोकने के साथ, जनता की फोन और कंप्यूटर के माध्यम से सारी गोपनीय जानकारीयां विश्व स्तर पर सार्वजनिक होने से रोका जा सके।

3. आधार कार्ड की शासकीय कार्यों में, रेलवे, हवाई यात्रा, मोबाइल फोन बैंक खाता खोलने, चलाने उसको पैन कार्ड से जोड़ने की आवश्यकता को खत्म किया जाएगा। ताकि आम आदमी की जानकारी दूसरी निजी कंपनियों के पास जाने से रोका जा सके और उसके साथ भविष्य में उसके साथ किसी प्रकार की जालसाजी छल कपट कोई गिरोह ना कर सके।

4. पूरे देश में हर शासकीय सेवाओं में परीक्षाओं से हर 3 साल में पदोन्नति दी जाएगी।

5. शासकीय कार्यालयों में आउटसोर्सिंग व संविदा नियुक्ति बंद कर हर पद पर परीक्षा के बाद हर साल 25 लाख नियुक्तियों की जाएगी।

6. देश के प्राकृतिक व मानव निर्मित सभी संसाधनों को निचोड़ने, उनका घोर शोषण करने, पहले उन्हें कर्ज में लादकर फिर उन पर कब्जा जमाने के लिए विश्व व्यापार संगठन बनाम विश्व व्यापार आतंकी संगठन जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देश और दुनिया को अपने तरीके से मनचाहा मोटा लाभ कमाने और गुलाम बनाने का अंतरराष्ट्रीय संगठन है। को ना केवल भारत से वरन विश्व से समाप्त करवा दिया जाएगा। जिसकी शुरुआत मैंने अपने समाचार पत्रों से सन 2002-3 से कर दी है। जिसके सार्थक परिणाम सुधी पाठकों में समाचार पत्रों में पढ़े होंगे।

7. बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर पूरी दुनिया में 1965 के बाद सभी लोकतांत्रिक देशों में, वहां के मंत्रियों और अधिकारियों को खरीद कर लादे गये सारे कानून जिसमें बीज अधिनियम 1966, कीटनाशक अधिनियम 1967, एकाधिकार एवं व्यापार प्रतिबंध अधिनियम 1970, आयोडीन नमक अधिनियम 1971, से लेकर सबसे खतरनाक कानून खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2005 तक सभी को खत्म करवाने का प्रयास किया जाएगा ताकि आम देश के नागरिकों के व्यवसाय को, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

8. हमारी आने वाली पीढ़ी की शिक्षा के लिए दसवीं कक्षा तक गुरुकुल की शिक्षा पद्धति निशुल्क विकसित की जाएगी। सभी निजी शिक्षण संस्थानों पर कानून बनवा कर उनकी शिक्षा गुणवत्ता और शिक्षण शुल्क की अनाप-शनाप बसूली को नियंत्रित व नियमित किया जाएगा।

9. 10 हजार करोड़ से ज्यादा की सभी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने के साथ सभी 1000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करने वाली सभी कंपनियों का 6 माही सरकारी अंकेक्षण अनिवार्य किया जाएगा ताकि पूंजी पतियों की जनता का धन हजम करने की व लूटपाट करने की गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके।

10. देश में हर वर्ष शासकीय संस्थानों, पुलिस, सेना, शिक्षा, बैंकों, बीमा, कंपनियों, रेलवे विद्युत मंडल आदि में 25 लाख नौकरियां हर वर्ष दी जाएंगी। साथ ही हर वर्ष 10 लाख से ज्यादा भ्रष्ट कामचोर सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों को बाहर भी किया जाएगा। ताकि शासकीय कार्यों में भ्रष्टाचार लापरवाही को नियंत्रित किया जा सके।

11. जल थल वायु सेना के लिए सभी प्रकार के हथियार विमानों, विमानवाही पोत, टैंक, मिसाइल, राडार, आदि का निर्माण भारतीय कंपनियों में ही किया जाएगा। इससे न केवल भारत की जरूरत बरन अन्य देशों को हथियार निर्यात करने का प्रयास किया जाएगा।

12. पर्यावरण के सुधार और बनो की हरियाली के विकास के लिए आमजन को भी जोड़ा जाएगा ताकि वनों के प्रति आम जन का ना केवल रुझान बढ़े और वनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

13. देश में गूगल व अन्य विदेशी एंड्राइड मोबाइल कार्यप्रणाली कंपनियों ने जो देश के लगभग 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल धारकों का व्यक्तिगत व निजी जानकारीयां एकत्रित कर, उनके बैंक खातों में सेंध लगाना। जानकारीयां के आधार पर उनका व्यवसायिक उपयोग

करना, करती है। को तत्काल बंद कर देश में ही सबसे पहले अपना सर्वर विकसित कर गूगल की तरह का जानकारी उपलब्ध करवाने से लेकर अन्य तरह के संसाधनों का विकास कर देश की जनता की डाटा को सुरक्षित रखना, किया जाएगा।

14. देश की न्यायिक व्यवस्था में, सभी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ईमानदार और कार्यक्षम जिला न्यायालयो न्यायाधीशों की परीक्षा के आधार पर पदोन्नति कर पदस्थ किया जाएगा। ताकि ईमानदारी से देश के सभी नागरिकों को न्याय की शीघ्र व्यवस्था की जाएगी।

15. इंग्लैंड के साथ किए गए आजादी के पट्टे के समझौते को श्याम दाम दंड भेद से समाप्त किया जाएगा। उसको दी जाने वाली 10 अरब डॉलर प्रतिवर्ष की राशि बंद की जाएगी व गौ मांस निर्यात बंद किया जाएगा। ना मानने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉमन वेल्थ के देशों के साथ मिलकर इंग्लैंड की दादागिरी वार्षिक पट्टे की रकम को देना बंद किया जाएगा ना मानने पर इंग्लैंड पर आक्रमण के साथ वेद मंत्रों और जनता की मस्तिकक्षीय तरंगों से पूरा इंग्लैंड डुबोने का प्रयास किया जाएगा।

विश्व संगठन बनाम विश्व षडयंत्रकारी संगठन

16. UNO संयुक्त राष्ट्र संघ बनाम संयुक्त शैतान संघ जो दुनिया के छोटे व गरीब देशों, उनके प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल गैस या उच्चस्तरीय खनिज भंडारों से युक्त है उन पर यूरोप की बहुराष्ट्रीय कंपनियों वहां की सरकारों को खरीदकर कानून लादकर अपना माल बेचने और वहां के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने लाभ के लिए करने के लिए करती हैं। एकाधिकार पद्धति खत्म की जाएगी।

17. WTO विश्व व्यापार संगठन बनाम विश्व व्यापार आतंकी संगठन भी इसी प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों का षडयंत्रकारी संगठन है। जिसका उद्देश्य भी वहां की सरकारों को खरीदकर कानून बनवा कर जैसा कि भारत में fssai कानून लादकर अपने शॉपिंग मॉल्स स्थापित कर क्षेत्रीय व्यापारियों लघु उद्योगों वहाँ की कृषि भूमि पर कब्जा कर देश की खाद्य व्यवसाय से जुड़े 30 से 40% लोगों को बेरोजगार बनाकर अपना यांत्रिक कृषि से उत्पादित माल बेचकर 200 से 500% तक लाभ कमाना होता है। शीघ्र समाप्त किया जा कर भारत में पुनः भारतीय खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 लागू किया जाएगा।

18. WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन बनाम विश्व स्वास्थ्य बिगाड़ वसूली संगठन जो कि पहले fssai जैसे कानूनों के माध्यम से विषैले रसायनों को खाद्य पदार्थों में मिलावट कर व अन्य तरीकों से मधुमेह, रक्तचाप, कैंसर, किडनी, लीवर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां फैलाता है। बदले में पूरी दुनिया के साथ भारत में हजारों करोड़ की मशीनें व दवाइयां बेचकर मोटी कमाई करता है, के षडयंत्रों को नष्ट कर देश में योग और आयुर्वेदिक पद्धति से स्वास्थ्य जीवन का मंत्र सिखाया जाएगा।

कृषि सुधार व विकास

19. क्षेत्रीय स्तर पर हर जिले में हर कृषि उत्पादन व सब्जियों फल फूलों मसालों आदि के प्रसंस्करण के लिए सहकारी क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाइयां खोली जाएंगी जो शीघ्र नष्ट होने वाली सब्जियों फल फूलों आदि का प्रसंस्कृत कर निर्यात योग्य बनाएंगे। जिससे किसानों को भरपूर लाभ मिले और उन्हें कर्ज में फंस कर आत्महत्या न करनी पड़े। प्रारंभ किया जाएगा।

20. भूमि स्वामी किसानों को प्रति दो एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि पर ऋण देकर दो गाय या भैंस दुधारू पशु रखना अनिवार्य किया जाएगा। जिससे ऐसे मवेशियों से दूध उत्पादन के साथ प्राप्त गोबर गोमूत्र से खाद व कीटनाशक तैयार किया जा सके। और इस प्रकार जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। हर हाल में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अगले 5 साल में समाप्त करने का कार्य किया जाएगा।

26. राष्ट्र की सुरक्षा के साथ किसानों, कृषि भूमि, छोटे-मोटे सब्जी के ठेले लगाने वालों, किराना व्यापारियों लघु उद्योगों, नमकीन मिठाई आदि की दुकानों, छोटे खाद्य उद्योगों, आदि सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 शीघ्र समाप्त किया जा कर भारत में पुनः भारतीय खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 लागू

किया जाएगा।

28. क्षेत्रीय स्तर पर हर जिले में हर कृषि उत्पादन व सब्जियों फल फूलों मसालों आदि के प्रसंस्करण के लिए सहकारी क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाइयां खोली जाएंगी जो शीघ्र नष्ट होने वाली सब्जियों फल फूलों आदि का प्रसंस्कृत कर निर्यात योग्य बनाएंगे। जिससे किसानों को भरपूर लाभ मिले और उन्हें कर्ज में फंस कर आत्महत्या न करनी पड़े प्रारंभ किया जाएगा।

29. भूमि स्वामी किसानों को प्रति दो एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि पर दो गाय या भैंस दुधारू पशु रखना अनिवार्य किया जाएगा। जिससे ऐसे मवेशियों से दूध के साथ के गोबर गोमूत्र से खाद व कीटनाशक तैयार किया जा सके। और इस प्रकार जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा।

हर हाल में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अगले 5 साल में समाप्त करने का कार्य किया जाएगा।

बैंकिंग एवं बीमा बैंकिंग सेक्टर

30. सभी सरकारी बैंकों में खोले गए बचत खातों पर धन निकासी और जमा करने पर लगाए जाने वाले सारे लेनदेन शुल्क को समाप्त किया जाएगा।

31. सरकारी बैंकों में दिए जाने वाले हर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋणों पर शासकीय केंद्रीय कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की अंकेक्षण टीम से उसका अंकेक्षण करवा कर ही ऋण दिया जाएगा।

31. बैंकों की सतत समीक्षा और नियमित अंकेक्षण संयुक्त रूप से रिजर्व बैंक के साथ सीएजी से भी करवाई जाएगी। ताकि जनधन जो बैंक में जमा है। उसकी सुरक्षा होने के साथ-साथ बैंकों की सुरक्षा भी की जा सके।

32. निजी बैंकों में भी रिजर्व बैंक और सीएजी का संयुक्त ऑडिट हर हाल में हर साल किया जाएगा ताकि निजी बैंकों की हालत सुधारने के साथ जनता का धन उसमें सुरक्षित रखा जा सके।

33. सभी संयुक्त कंपनियों व निजी कंपनियों में जहां कुल प्रदत्त पूंजी का 25% तक बैंक ऋण होगा वहां पर ऋण प्रदाता बैंक द्वारा अपना एक संचालक कंपनी के संचालक मंडल में नियुक्त किया जाएगा। जो कंपनी की आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने के साथ दिए गए बैंक ऋण की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होगा।

34. सभी शासकीय व निजी बीमा कंपनियों में भी 500 करोड़ से ऊपर की देनदारीओं व बीमा प्रीमियम पर वित्त मंत्रालय का व सीएजी का एक अधिकारी संचालक मंडल में नियुक्त किया जाएगा। जो बीमा धारकों के हितों से लेकर उनकी कार्य पद्धति पर भी निगरानी करेगा।

35. 3 वर्ष तक नियमित बैंकिंग ऋणों की किस्त व नियमित लेन-देन न होने पर बैंक तत्काल उन संचालकों की निजी व अन्य कंपनियों की संपत्ति को जप्त कर अपने ऋणों की वसूली करने के लिए तत्काल स्वतंत्र होंगे।



अजमेरा एस. प्रवीण कुमार

इंदौर लोकसभा क्षेत्र से आपके अपने प्रत्याशी

ट्रेक्टर चलाता किसान वाला बटन दबाकर अजमेरा एस. प्रवीण कुमार को भारी मतों से विजयी बनाएं